



रेफरेंस संख्या -2020//pks/04

E-Newsletter, Issued in Public Interest

बुधवार, 15 अप्रैल 2020

राजस्थान सरकार पहना रही गुजरात के अवैध शराब की बिक्री के मॉडल को विधिक जामा।

वित्त सचिव राजस्थान सरकार द्वारा जारी किया गया अजीबोगरीब आदेश।

राजस्थान सरकार
वित्त (आबकारी) विभाग

क्रमांक प.4(1)वित्त/आब0/2020

दिनांक: 14 अप्रैल, 2020

- आयुक्त, आबकारी विभाग, राजस्थान
- महाप्रबंधक, राज0 स्टेट गंगानगर शुगर मिल्स लि0, जयपुर
- कार्यकारी निदेशक राज0 स्टेट ब्रेवरीज कॉर्पोरेशन लि0, जयपुर

आदेश

वर्ष 2020-21 हेतु आबकारी बन्दोबस्त की प्रक्रिया पूर्ण होने को है। कोविड-19 की वजह से प्रदेश में 22 मार्च, 2020 से शराब की दुकानें बंद हैं। जिसकी वजह से राज0 स्टेट ब्रेवरीज कॉर्पोरेशन एवं राज0 स्टेट गंगानगर शुगर मिल्स के विभिन्न स्थानों पर स्थित गोदाम या डिपो हैं जो देशी व भारत निर्मित विदेशी शराब से भरे हैं। साथ ही जिन गोदामों में जगह की कमी है उन गोदामों या डिपो के बाहर भी शराब से भरे हुए सैंकड़ों ट्रक खड़े हैं। उनके चोरी होने व उससे राजस्व हानि होने की भी संभावना है। जिनकी सुरक्षा भी एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि गोदाम या डिपो के बाहर जो शराब से भरे ट्रक खड़े हैं उनको तत्काल खाली कर यथासम्भव गोदाम में रखा जावे साथ ही जिन लाइसेंसधारियों के पास दुकान एवं गोदाम में पर्याप्त भण्डारण की व्यवस्था है उनकी मांग पर शराब निर्गमित की जा सकती है बशर्ते कि अग्रिम आदेश तक इस शराब का उपभोक्ताओं को किसी भी तरह से विक्रय नहीं करेंगे। उपरोक्त के संबंध में चालान, परमिट जारी करने एवं राजकोष में राजस्व नियमानुसार जमा होना सुनिश्चित करें। इस संबंध में विशेष ध्यान रखा जाएगा कि जो क्षेत्र कर्पूरुयस्त घोषित है, उन क्षेत्रों के मदिश लाइसेंसधारियों को शराब का निर्गमन नहीं किया जाए। शराब के लोडिंग व अनलोडिंग के उपरोक्त कार्य में कोविड-19 के मध्यनजर राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार द्वारा जारी गाईडलाइन व आदेशों की पूर्ण एवं सख्ती से पालना की जावे।

यह आदेश सक्षम स्तर से स्वीकृत है।

(डॉ० पृथ्वी)
शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त विभाग।
- शासन सचिव एवं आयुक्त, परिवहन विभाग, राजस्थान सरकार।
- पुलिस आयुक्त, जयपुर एवं जोधपुर।
- समस्त जिला कलेक्टर, राजस्थान।
- समस्त पुलिस अधीक्षक, राजस्थान।

संयुक्त शासन सचिव

दिनांक 14/04/2020 को वित्त विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा एक अजीबोगरीब आदेश जारी किया गया, जिसमें कहा गया कि राजस्थान स्टेट ब्रेवरीज कारपोरेशन और राजस्थान स्टेट गंगानगर शुगर मिल्स के गोदामों और डिपो शराब से भरे हुए हैं, साथ ही कई जगह शराब के सैंकड़ों ट्रक भी खड़े हुए हैं, जिनमें चोरी होने से राजस्व की हानि होने का डर है अतः इस शराब को उन लाइसेंसियों की दुकानों और गोदामों में निर्गमित की जा सकेगी जिनके पास पर्याप्त जगह

BREAKING NEWS

st
इंडिया
राजस्थान

आखिर क्यों लगातार अजीबोगरीब फैसले कर रहा आबकारी विभाग ?

अव्यावहारिक आबकारी नीति को लेकर विभाग पहले ही आ चुका चर्चा में, अब सरकारी गोदाम के अंदर और बाहर रखी शराब को लाइसेंस को देने के आदेश, मतलब लाइसेंस को शराब की सप्लाई भी और बेचने पर रोक भी, सरकारी गोदामों से लाइसेंस की दुकान, गोदाम में शराब पहुंचाने के आदेश, इधर लाइसेंस की चिंता जब बेचनी ही नहीं तो आफत क्यों लें मूल ? क्या सरकार लेगी शराब चोरी न होने की गारंटी ? क्या लाइसेंस को शराब हंड ओवर करने से नहीं टूटेगी लॉक डाउन की भावना ? वित्त सचिव (आबकारी) के इस निर्णय की आलोचना, शराब हाथ में रखो लेकिन बेचो मत, क्या मुख्यमंत्री सचिवालय के ध्यान में है ये सबकुछ ?

शासन सचिव, वित्त विभाग का विवादित आदेश,

साभार:-फर्स्ट इंडिया राजस्थान द्वारा वायरल किया गया मैसेज



राजस्व पर भी तो ध्यान दो सरकार!!!

सख्ती के बावजूद धड़ल्ले से हो रही अवैध शराब की बिक्री! राजस्व को पहुँच रही हानि!!

ये से चार गुनी रेट पर ब्लैक में बेच रहे शराब ब्यपारी!

कई दिनों से समाचार पत्रों में पढ़ने में आ रहा था कि लॉकडाउन में शराब की दुकानों पर चोरी की घटनाएं बढ़ गयी हैं। लेकिन जब आज के समाचार पत्र में इन खबरों की पोल खुली तो सारा माजरा समझ में आ गया। सरकार ने जब लॉकडाउन की घोषणा की थी उस समय वित्तीय वर्ष समाप्त होने में केवल कुछ दिन ही शेष थे, जिसके चलते पुराने लाइसेंसों की अंतिम तिथि भी चोरी की घटनाओं में आ गई। सरकार ने जब लॉकडाउन की घोषणा की तो उस समय वित्तीय वर्ष समाप्त होने में केवल कुछ दिन ही शेष थे, जिसके चलते पुराने लाइसेंसों की अंतिम तिथि भी चोरी की घटनाओं में आ गई। सरकार ने जब लॉकडाउन की घोषणा की तो उस समय वित्तीय वर्ष समाप्त होने में केवल कुछ दिन ही शेष थे, जिसके चलते पुराने लाइसेंसों की अंतिम तिथि भी चोरी की घटनाओं में आ गई।

लॉकडाउन के दौरान भी शराब बिक्री को लेकर पुलिस में सख्ती है। पुलिस पर भी मिलीभगत के आरोप लग चुके हैं। ऐसे में पुलिस अधिकारियों ने अवैध रूप से शराब बेच रहे लोगों पर कठोर कार्रवाई के लिए कहा है।

असोक गुप्ता, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक

साप्ताहिक-राजस्व पत्रिका में दिनांक 12/04/2020 को प्रकाशित खबर

मुनाफा कमा लिया जो उन्हें शराब की ओवररेट, सरकार की सख्ती के चलते बंद होने से, नहीं हो रहा था।

ब्लैक के इस धंधे में, जो शराब ब्यवसायी पुलिस की सख्ती के कारण माल नहीं निकाल पा रहे थे उन्होंने अपनी ही दुकानों में चोरियाँ करवाने की चालू कर दी, जिससे ना तो सरकार को हिसाब देना पड़े और ब्लैक करने से जो मुनाफा होने सो अलग।

पिछली पोस्ट में हमारे द्वारा उठाया गया यह मुद्दा

पता:-S 6151 पृष्ठ 1

हैं। परन्तु यह लाइसेंसों को इस शराब को उपभोक्ताओं को अग्रिम आदेश तक विक्रय नहीं करेंगे।

खुद के यहाँ चोरी का डर, मानो शराब लाइसेंसियों की दुकाने पुलिस पहरे में।

राज्य सरकार का यह आदेश सबको हैरत में डाल रहा है, लोगो का कहना है कि यदि सरकार को ही चोरी का डर सता रहा है तो आम लोगो का क्या होगा? क्या सरकार करोड़ों रुपयों के सामान के लिए सुरक्षा इंतजाम उपलब्ध नहीं करवा सकती? सरकार तो मानो यह सोच रही है कि लाइसेंसियों की दुकाने पुलिस पहरे में है और उनके यहाँ चोर घुस ही नहीं सकते।

बिल्ली को दूध की रखवाली

जानकारो का मानना है कि यह तो बिल्ली को दूध की रखवाली वाला मुहावरा चरितार्थ करने वाली बात हो गयी है। भला लाइसेंसों बिना नफे के यह आफत मौल क्यों लेंगे? यह तो चोरी छुपे ब्लैक में बेचने की छुट देने के

समान है। इससे शराब लाइसेंसों लॉकडाउन में ही पूरे साल का मुनाफा शराब की ब्लैक करके कमा लेंगे। अभी ब्लैक मार्केट में शराब की बोतल के 2 गुने से 10 गुने तक वसूली की जा रही है।

सरकार को अपनी छवि खराब होने का डर

इस आदेश के पीछे सरकार के मन के डर को साफ़ देखा जा सकता है, अपनी गांधीवादी छवि को लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री महोदय काफी एतियात बरत रहे हैं वह शराब की दूकान खोलने का आदेश देकर विपक्ष को कतई यह मौक़ा नहीं देना चाहते हैं वह उनकी गांधीवादी छवि पर ऊंगली उठाये परन्तु वह कोरोना की वजह से इस वित्तीय संकट में शराब की बिक्री से आने वाले राजस्व को भी नहीं खोना चाहते हैं, जिसके चलते ही सरकार ने बीच का मार्ग अपनाया है। परन्तु सरकार के इस कदम को प्रदेश में गुजरात में चल रहे अवैध शराब की बिक्री के मॉडल को विधिक जामा पहनाने की कोशिश माना जा रहा है।

लॉकडाउन 2.0 में केन्द्रीय सरकार ने शराब की बिक्री नहीं करने को कहा।

आज भारत सरकार द्वारा जारी की गयी गाईडलाइन में सरकार ने स्पष्ट किया है कि 20 अप्रैल के बाद छुट देने वाले उपक्रमों में शराब, सिगरेट और गुटखे की बिक्री को छुट नहीं दी जाए। ऐसे में उन लोगो के सामने निराशा छा गयी है जो यह सोच रहे थे कि सरकार शराब की बिक्री को लॉक डाउन से छुट देगी परन्तु दोनों सरकारों के इन निर्णयों ने शराब ब्लैक करने वालो की पाँचों उँगलियाँ घी में और सर कढाई में कर दिया है और शराब उपभोक्ताओं के सामने आफत खड़ी कर दी है।